

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास विभाग
संख्या-175/IV(2)-श0वि0-07-223(सा0)/06
देहरादून : दिनांक-17 सितम्बर, 2007

कार्यालय-झाप

उत्तराखण्ड के शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार अथवा रोजगार अपनाकर जीविकोपार्जन हेतु राज्य सरकार द्वारा "सार्वभौम रोजगार योजना" प्रारम्भ की गयी है, जिसके संचालन हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्गत किये जाते हैं :-

सार्वभौम रोजगार योजना

1- प्रस्तावना:-

उत्तराखण्ड के नगरीय क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक ससाधनों, सामाजिक एवं निजी परिसम्पत्तियों एवं स्थानीय रूप से उपलब्ध जनशक्ति एवं सामाजिक पूंजी पर आधारित यह रोजगार योजना ऐसे इच्छुक शिक्षित, अर्द्धशिक्षित एवं अशिक्षित युवक/युवतियों, पुरुषों एवं स्त्रियों को लक्षित करती है जो स्थानीय रूप से स्वरोजगार अथवा रोजगार अपनाकर जीविकोपार्जन करना चाहते हैं।

2- योजना क्षेत्र:-

सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य का नगरीय क्षेत्र।

3- पात्रता:-

नगरीय परिवार का कोई भी एक व्यस्क सदस्य जो केन्द्र अथवा राज्य द्वारा प्रायोजित एवं सहायित किसी भी ऋण सह अनुदान, स्वरोजगार/रोजगार योजना का लाभार्थी न हो एवं सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र में नियमित रूप से सेवायोजित न हों एवं स्वरोजगार हेतु इच्छुक हों।

4- आरक्षण:-

योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को न्यूनतम प्रतिशत क्रमशः 19 व 4 रहेगा। कुल लाभार्थियों में कम से कम 33 प्रतिशत महिलायें तथा 3 प्रतिशत विकलांग होंगे।।

5- अनुमन्यतायें:-

परियोजना प्रस्ताव के अनुसार चयनित क्रियाकलाप/ गतिविधि के लिए प्रथम वर्ष में प्रति व्यक्ति ₹0 7000/- (₹0 सात हजार मात्र) की सीमा तक अनुदान।

द्वितीय वर्ष में चयनित रोजगार क्रियाकलाप/गतिविधि की सफलता पर आधारित अधिकतम ₹0 5000/- (₹0 पांच हजार मात्र) का प्रोत्साहन अनुदान।

तृतीय व अन्तिम वर्ष में चयनित रोजगार क्रियाकलाप/गतिविधि के सफल संचालन पर अधिकतम ₹0 3000/- (₹0 तीन हजार मात्र) का प्रोत्साहन अनुदान।

परन्तु अनुदान की राशि किसी भी दशा में परियोजना लागत की 50 प्रतिशत राशि से अधिक नहीं होगी। परियोजना राशि के शेष भाग का निवेश लाभार्थी द्वारा स्वयं किया जा सकता है अथवा वह इस हेतु बैंक से ऋण ले सकता है। बैंक ऋण की सीमा व्यक्तिगत स्वरोजगार योजनाओं में यथा निर्धारित होगी। बैंक वित्त पोषण को प्राथमिकता दी जायेगी। स्नातक अथवा उससे अधिक शिक्षित लाभार्थियों के अतिरिक्त प्रोत्साहन कुल देय अनुदान का 10 प्रतिशत होगा।

जिन मामलों में अनुदान 3 के बजाय दो वर्ष में आवश्यक व अनिवार्य समझे जाये, ऐसे मामलों में जनपद समिति संस्तुति कर सकती है। जिस पर राज्य स्तर पर सचिव की अध्यक्षता में समिति विलम्बतम् एक माह के भीतर अपना निर्णय प्रेषित करें। यह निर्णय अन्तिम निर्णय होगा।

6- रोजगार क्रियाकलाप/गतिविधियां:-

1-	टी0वी0/रेडियो/रेफ्रिजरेटर/आटोमोबाईल/डीजल मोटर/ बिजली के घरेलू सामान की मरम्मत
2-	गृह निर्माण सम्बन्धी कौशल जैसे प्लम्बिंग/बढ़ई/राज भिस्त्री/पोलिसिंग/टाईल लगाना/शीशा लगाना/ इलैक्ट्रिकल्स कार्य आदि
3-	लघु उत्पादन इकाईयां वाशिंग पाउडर, अगरबत्ती, मोमबत्ती चूड़ियां, गारमेंट्स, प्लास्टिक के खिलाँने, फुटवीयर, वूडन/स्टील फर्नीचर, साडी प्रिन्टिंग, बुनाई, पोटर्री, लोहार, बर्तन/लोहे का सामान, खाद्य प्रसाधन, बाल पेन बनाना आदि
4-	कुम्हार, मोची, बढ़ईगिरी, लोहारगिरी जैसे अन्य कार्य
5-	अन्य कोई ऐसा क्रियाकलाप अथवा गतिविधि जिसे राज्य सरकार योजना के प्रयोजनार्थ सम्मिलित करें।

जनपद विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप और योजनायें सम्मिलित करने हेतु जिला समितियां अधिकृत होगी किन्तु जिला समिति यह पुष्टि करे कि प्रस्ताव योजना के उद्देश्यों के अनुरूप ही हैं तथा जनपद विशेष में प्रभावी रोजगार की दृष्टि से प्राथमिकता का है।

7- नोडल विभाग एवं जिले का नोडल अधिकारी:-

इस योजना का नोडल विभाग राज्य नगरीय विकास अभिकरण होगा। जिले में जिलाधिकारी इस योजना के नोडल अधिकारी होंगे। क्रियान्वयन में सुगमता के लिए जिलाधिकारी कतिपय अथवा समस्त अधिकार मुख्य विकास अधिकारी के पक्ष में प्रतिनिधानित कर सकेंगे।

8- आवेदन एवं आवेदनों का निस्तारण:-

इच्छुक पात्र स्वरोजगार व्यक्ति चयनित आर्थिक क्रियाकलाप/गतिविधि, उपलब्ध प्राकृतिक, सार्वजनिक व निजी संसाधनों एवं जन शक्ति व सामाजिक पूंजी का उल्लेख करते हुए आवेदन उप नगर अधिकारी, नगर निगम/अधिशारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के माध्यम से जिलाधिकारी अथवा मुख्य विकास अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। चयनित क्रियाकलाप/गतिविधि

की सम्भावनाओं के आधार पर नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत परियोजना प्रस्ताव 15 दिवस के भीतर सम्पूर्णता में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी को स्वीकृतार्थ प्रस्तुत करेंगे। परियोजना प्रस्तावों के परीक्षण एवं उन पर संस्तुति हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्न समिति विचार करेगी:-

क्र०सं०	जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष
1-	जिला मुख्यालय की नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के उप नगर अधिकारी/अधिशाली अधिकारी	सदस्य सचिव
2-	सम्बन्धित नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के उप नगर अधिकारी/अधिशाली अधिकारी	सदस्य
3-	महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
4-	जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक	सदस्य

परियोजना प्रस्ताव पर अंततः स्वीकृति जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी। बैंक से वित्त पोषण वांछित होने की स्थिति में परियोजना प्रस्ताव की एक-एक प्रति सम्बन्धित बैंक की शाखा एवं जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक को प्रेषित की जायेगी। सम्बन्धित बैंक की शाखा द्वारा एक माह के भीतर परियोजना प्रस्ताव पर निर्णय लिया जायेगा। बैंक से स्वीकृति प्राप्त होने की स्थिति में अनुदान की राशि सम्बन्धित शाखा को भेज दी जायेगी। अनुदान की राशि पर न तो ब्याज देय होगा और न ही ब्याज वसूला जायेगा। अनुदान की राशि का समायोजन back ended subsidy के रूप में निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जायेगा।

परियोजना प्रस्ताव के अनुसार परियोजना राशि सम्बन्धित बैंक शाखा द्वारा एक मुश्त अथवा दो किस्तों में कार्यान्वयन की सफलता के आधार पर लाभार्थी के खाते में अवमुक्त की जायेगी। बैंक अधिकारी एवं नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अधिशाली अधिकारी परियोजना के विभिन्न चरणों का निरीक्षण व परीक्षण कर सकेंगे।

परियोजना राशि के दुरुपयोग की स्थिति में ऋण की अवशेष राशि एवं अनुदान की सम्पूर्ण राशि सब्याज भू-राजस्व की बकाया राशि की भांति वसूली जा सकेगी।

9- योजना की अवस्थापना:-

इस योजना के लिए योजना अवस्थापना की कोई पृथक व्यवस्था नहीं की जा रही है। चयनित क्रियाकलाप/गतिविधि के अनुसार नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत द्वारा संचालित स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना अवस्थापना का लाभ इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु उठाया जा सकता है।

10- प्रशिक्षण:-

जिले में अवस्थित स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना एवं मिलती जुलती योजनाओं का संचालन करने वाले विभागों के चालू प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इस योजना के लाभार्थियों को सम्मिलित किया जा सकता है।

योजनान्तर्गत लाभार्थियों की कौशल वृद्धि हेतु धनराशि की व्यवस्था की जायेगी। इस हेतु बजट व्यवस्था में 05 प्रतिशत धनराशि मात्राकृत की जायेगी।

11- सम्बन्धित विभागों की प्रतिबद्धता:-

चयनित क्रियाकलापों से सम्बन्धित विभाग इस योजना के क्रियान्वयन के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध होंगे। जिलाधिकारी असहयोग करने वाले विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध स्वयं कार्यवाही के लिए सक्षम होंगे। उचित प्रकरणों में ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध शासन स्तरीय कार्यवाही की संस्तुति शासन को की जायेगी।

12- पूर्वगामी एवं पश्चगामी अन्तर्सम्बन्धन:-

जिले में अवस्थित सम्बन्धित विभागों एवं नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के चालू कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपलब्ध ऐसे अन्तर्सम्बन्धों का लाभ इस योजना के अधीन लिया जा सकेगा।

13- अनुश्रवण एवं मूल्यांकन:-

शासन स्तर पर इस योजना की समीक्षा एवं अनुश्रवण अन्य विकास योजनाओं की भांति किया जायेगा।

जिलाधिकारी प्रतिमाह योजना के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा कर मासिक प्रगति विवरण राज्य नगरीय विकास अभिकरण, देहरादून के माध्यम से शासन को भेजेंगे। राज्य नगरीय विकास अभिकरण, मासिक विवरण प्रपत्र निर्धारित कर जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेगा। क्रियान्वयन के आरम्भिक वर्षों में प्रत्येक जिलाधिकारी से यह अपेक्षित होगा कि वे योजना के और अधिक प्रभावी एवं सफल क्रियान्वयन एवं कठिनाई निवारण हेतु सुझाव शासन को प्रेषित करते रहें।

फील्ड स्तर पर योजना के क्रियान्वयन के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वयं पर्याप्त संख्या में सत्यापन एवं मूल्यांकन किया जायेगा। सत्यापन मानक निम्नवत् है:-

क्र०सं०	अधिकारी का नाम पदनाम	सत्यापन का प्रतिशत
1-	जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/ जिला मुख्यालय की नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के उप नगर अधिकारी/अधिशाली अधिकारी	10 प्रतिशत
2-	अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी	20 प्रतिशत
3-	सम्बन्धित नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के उप नगर अधिकारी/अधिशाली अधिकारी	शत प्रतिशत

(शत्रुघ्न सिंह)
सचिव।

सं०- 175 (1)/IV(2)-श०वि०-07, तददिनांक। 17/9/07

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय/राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, आवेरोय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- 7- मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
- 8- रामस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 9- मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम देहरादून।
- 10- अधिशासी अधिकारी, रामस्त नगर निकाय उत्तराखण्ड।
- 11- निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 12- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

रामा

(मायावती ढकरियाल)

अनु सचिव।